(b) the garments out of the above which were exported during the last three year; and

(c) the garments which were exported to hard currency areas?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Production of garments is the small scale sector. No accurate assessment on he quantum of production of garments is therefore available.

(b) and (c) Export figures are neither monitored nor maintained on a state-wise basis.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

485. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों के कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरु की गयी है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर 1992 तक इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की इच्छा प्रकट करने वाले सेवा निवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी-वार जैसे मशीनमैन लिपिकीय और प्रबंधक कर्मियों आदि की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा दबाव डाल कर सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां,

(ख) 31 अक्टूबर 1992 तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 248 अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 10,380 कामगारों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया है।

(ग) और (घ) एन टी सी के कर्मचारियों पर दबाव डाल कर सेवा निवृत्ति के लिए उन्हें बाध्य करने की कोई भी शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान धागा नीति में परिवर्तन

486. **डॉ० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कि देश में हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों को सस्ते दाम पर धागा उपलबध करवाने के लिह सरकार वर्तमान धागा नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना असंगठित क्षेत्र के बुनकरों के लिए कोई नये प्रावधान किये गये है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है, और

(ङ) क्या यह भी सच है कि असंगठित क्षेत्र के बुनकरों की संख्या संगठित क्षेत्र के बुनकरों से ज्यादा है, यदि हां, तो उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में सूत की आपूर्ति के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सरकार समय-समय पर समीक्षा करती है। मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक संशोधित योजना अभी हाल ही में आरंभ की गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के तत्वावधान में कार्यान्वित मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की योजना में कहा गया है कि राज्य हथकरघा अभिकरणों जैसे राज्य हथकरघा विकास निगम और राज्य शीर्ष-क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों में पंजीकृत बुनकरों की सूत की आपूर्ति की जाए। इस योजना में राज्य हथकरघा अभिकरणों में अंतर्गत शामिल व्यक्तिगत बुनकरों को भी शामिल किया गया है। अपर्याप्त संगठनात्मक व्यवस्था और सूत आपूर्ति की प्रणाली में लीकेज़ होने की संभावना को देखते हुए प्राइवेट क्षेत्र के बुनकरों को इस योजना में शामिल करना संभव नहीं है।

(ङ) वर्ष 1987-88 में की गई राष्ट्रीय हथकरघा गणना के अनुसार देश में 22.43 लाख पूर्णकालिक बुनकर हैं जिसमें से 12.11 लाख बुनकर स्वतंत्र बुनकर है और 3.45 लाख मास्टर बुनकर के अंतर्गत हैं।

तथापि इसमें से कुछ हथकरघा अभिकरणों के माध्यम से रोजगार भी ले रहे हैं।

Conference of Handloom Weavers

487. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the massive conference of handloom weavers organised in Madras in May, 1992;

(b) if so, whether some measures have been suggested at the above conference for modernisation of handlooms and the rehabilitation of weavers; and

(c) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It was recommended, *inter-alia*, to enhance the quantum of assistance under modernisation of looms upto Rs. 10,000/-. Government has revised assistance available under the modernisation of looms scheme upwards. Assistance is available upto Rs. 8000/- for Jacquard/Pedal looms.

Government is in agreement with the general recommendation for extensive efforts of rehabilitation of the weavers and has provided adequate outlays for welfare and developmental schemes aimed at providing sustained and regular employment to the handloom weavers.

Group insurance scheme for powerloom, handloom, etc.

488. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to introduce Group Insurance Scheme for powerloom, handloom and similar other works in collaboration with the L.I.C. of India during 1992-93;

(b) if so, what are the details thereof and which Authority would administer the above schemes; and

(c) What is the expenditure likely to be earmarked for this purpose during 1992-93 indicating separately the shares of State Governments and Central assistance in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) As per the scheme approved by the Government of India, handloom and powerloom workers are eligible to get an insurance cover for Rs. 10,000 on an annual premium of Rs. 120 to be shared equally between the worker, the Central Government and the State Government. The Scheme would be administered by the State Government.

(c) There is a budget provision of Rs. 600 lakhs for the Handlooms and Rs. 75 lakhs for Powerlooms in the Government of India budget, Share of State Government will be as per number of workers covered.

Closure of sick textiles mills

489. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have prepared a plan to close down some of the sick textile mills in the country;

(b) if so, the number of sick textile mills which are proposed to be closed in different States, state-wise.

(c) the number of workers who are likely to be retrenched as a result thereof, State-wise.

(d) the compensation proposed to be given to the workers of the above sick textile mills.